Lecture 19:

Prof Nirmal Kr Singh
Associate Professor
Deptt of LSW
S.N.S.R.K.S College, Saharsa
Email: nirmalsingh245@gmail.com

Poverty (गरीबी)

Topics:

1. **निर्धनता के लिये उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Poverty)**
2. **निर्धनता के समाधान के लिए अनुकूल उपाय (Suitable Measures for Finding Solution of Poverty)**

 # 1. निर्धनता के लिये उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Poverty):

भारत में निर्धनता का अत्याधिक प्रसार है । इसके लिये उत्तरदायी मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:

1. तीव्रतापूर्वक बढ़ती हुई जनसंख्या (Rapidly Rising Population):

पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या 2.2 प्रतिवर्ष के दर से बड़ी है । औसतन 17 मिलियन लोग भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष जुड़ते हैं जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में पर्याप्त वृद्धि होती है ।

2. कृषि में कम उत्पादन (Less Productivity in Agriculture):

कृषि में उत्पादकता का स्तर खेतों के छोटे आकार, पूंजी का अभाव, कृषि की परम्परागत विधियों का उपयोग और निरक्षरता आदि के कारण है ।

3. अल्प प्रयुक्त साधन (Under Utilized Resources):

मानवीय साधनों के अल्प-रोजगार और अदृश्य बेरोजगारी तथा साधनों के अल्प उपयोग की उपस्थिति कृषि क्षेत्र में कम उत्पादन का कारण बनी है, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर नीचे आया है ।

4. कीमतों में वृद्धि (Price Rise):

निरन्तर बढती हुई कीमतों, विशेषकर खाद्य पदार्थों तथा पैट्रोल और डीजल की कीमतों, ने आम लोगों की मुसीबतों में वृद्धि की है । इससे समाज में बहुत थोड़े लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा निम्न वर्ग के लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई अनुभव करते हैं ।

5. बेरोजगारी (Unemployment):

बेरोजगार लोगों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या निर्धनता का एक अन्य कारण है । काम खोजने वालों की संख्या, रोजगार के अवसरों के विस्तार के दर के अनुपात में बड़ी है ।

6. सामाजिक कारक (Social Factors):

सामाजिक व्यवस्था अभी भी पिछड़ी हुई है तथा तीव्र विकास में सहायक नहीं है । उत्तराधिकार के नियम, जाति प्रथा तथा रीति-रिवाज तीव्र विकास के माँग में बाधा बन रहे हैं जिससे निर्धनता की समस्या और भी तीव्र हो गई है ।

7. राजनैतिक कारक (Political Factors):

अंग्रेजों ने भारत में अधूरे विकास की प्रक्रिया द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में उपनिवेशी राज्य बना दिया । उन्होंने अपने हितों के अनुकूल प्राकृतिक साधनों का शोषण किया और भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार को दुर्बल बना

दिया । स्वतन्त्र भारत में विकास योजनाएं राजनैतिक हितों से प्रेरित होती है । अतः निर्धनता और बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान में आयोजन असफल रहा ।

 # 2. निर्धनता के समाधान के लिए अनुकूल उपाय (Suitable Measures for Finding Solution of Poverty):

सामाजिक रूप में सुस्पष्ट निर्धनता न तो वांछनीय है और न ही सहनीय । पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सत्य ही कहा था, "किसी निर्धन देश में पुन: वितरण के लिये केवल निर्धनता ही होती है ।"

आय की असमानताओं को दूर करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय अति सहायक हैं:

1. रोजगार के अधिक अवसर (More Employment Opportunities):

रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करके निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है ताकि लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके । इस प्रयोजन से पूजी-गहन तकनीकों की तुलना में श्रम-गहन तकनीकें समस्याओं के समाधान में अधिक सहाय न, सिद्ध हो सकती हैं ।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मुलन के लिये अनेक कार्यक्रम जैसे सम्बद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम आदि आरम्भ किये गये ।

2. न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम (Minimum Needs Programme):

न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम निर्धनता कम करने में सहायक हो सकता है । यह तथ्य सत्तर के दशक के आरम्भ में महसूस किया गया जब वृद्धि के लाभ निर्धन लोगों को प्राप्त नहीं हुये तथा अल्प-विकसित देशों के पास समाज वे; निम्न वर्ग की मौलिक आवश्यकताओं की ओर सीधा ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पहली बार आरम्भ किया गया ।

3. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (Social Security Programme):

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे श्रमिकों का क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम तथा मृत्यु अयोग्यता अथवा कार्य के दौरान बीमारी आदि की स्थिति में अन्य लाभ निर्धनता पर प्रहार कर सकती है ।

4. लघु-स्तरीय उद्योगों की स्थापना (Establishment of Small Scale Industries):

कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की रचना में सहायक हो सकती है । इसके अतिरिक्त, इससे अधिक विकास वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ओर शहरीकरण की समस्या उत्पन्न किये बिना साधनों का स्थानान्तरण होगा ।

5. ग्रामीण लोगों की प्रगति (Uplift of Rural Masses):

कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है, अतः ग्रामीण निर्धनों की उन्नति के लिये विभिन्न योजनाएं आरम्भ की जानी चाहियें । गांवों में रहने वाले निर्धन प्रायः भूमिहीन कृषि श्रमिकों के परिवारों, छोटे और सीमान्त किसान, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बन्धित होते हैं । तथापि यह स्मरणीय है कि भारत सरकार ने समय-समय पर निर्धन लोगों की प्रगति के लिये अनेक योजनाएँ आरम्भ की हैं ।

6. भूमि सुधार (Land Reforms):

भूमि सुधारों का नारा है, "भूमि का स्वामी खेती करने वाला है ।" जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिये वैधानिक उपाय किये गये । मध्यस्थों तथा कृषि भूमि की सीमा निश्चित की गई । परन्तु, दुर्भाग्य की बात है कि इन भूमि सुधारों का उचित कार्यान्वयन नहीं हुआ । तब भी आशा की जाती है कि यदि इन सुधारों का गम्भीरता से कार्यान्वयन किया जाता है तो इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे जिससे समृद्ध वर्ग की आय कम करने में सहायता प्राप्त होगी ।

7. शिक्षा का प्रसार (Spread of Education):

शिक्षा, मानवीय शरीर, मन और आत्मा से सर्वोत्तम गुणों को बाहर लाने में सहायता करती है । इसलिये सब को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करना आवश्यक है निर्धन लोगों को छात्रवृति, निःशुल्क पुस्तकें और आकस्मिक भत्ते के रूप में विशेष सुविधाएं दी जानी चाहियें । शिक्षा निर्धन लोगों में जागृति लायेगी और उनकी मानसिक योग्यता को बढायेगी ।

8. सामाजिक और राजनीतिक वातावरण (Social and Political Atmosphere):

नागरिकों और राज-नेताओं के सक्रिय सहयोग के बिना भारत से निर्धनता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता । निर्धनता को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिये अनुकूल सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण आवश्यक है ।

9. न्यूनतम आवश्यकताएँ उपलब्ध करवाना (To Provide Minimum Requirement):

समाज के निर्धन वर्ग को न्यूनतम आवश्यकताएँ उपलब्ध करवाना निर्धनता की समस्या को दूर करने में सहायक हो सकता है । इसके लिये सार्वजनिक प्रापण और वितरण प्रणाली को सुधारना तथा दृढ़ बनाना आवश्यक है ।

----------*******The End*******----------